RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 26 JULY TO 01 AUGUST 2023 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 08 ■ अंक 45 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

भारत की जीडीपी को लगेंगे पंख Page 2

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 15 महीने के टॉप पर Page 3

महाराजा को 'टाटा' कहेगी एयर इंडिया Page 4

editoria!

पीएफ पर बढ़ी ब्याज दर बढ़ी

केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत ब्याज दर में आंशिक वृद्धि को मंजूरी दे दी है. यह वृद्धि पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जमा राशि से लागू होगी. पीएफ पर अब 8.15 प्रतिशत ब्याज दिया जायेगा. पिछले वर्ष यह 8.10 प्रतिशत था. इस घोषणा के बाद विभिन्न मीडिया माध्यमों में कर्मचारियों को फायदे की गणना समझायी जा रही है. दरअसल, सरकार ने पीएफ पर ब्याज वृद्धि के जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, वह इसी वर्ष मार्च में आया था. तब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पीएफ के ट्रस्टी बोर्ड ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के समक्ष ब्याज दर में मामूली वृद्धि की सिफारिश की थी. इसके बाद यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास गया और अब इस वृद्धि पर मुहर लग गयी है. कर्मचारी भविष्य निधि योजना भारत में सरकारी या निजी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों और उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा के उद्देश्य से बनायी गयी एक योजना है जो वर्ष 1952 में लागू की गयी थी. यह एक कोष है जहां कर्मचारियों का पैसा संग्रहित रहता है और उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के समय या विशेष परिस्थितियों में उससे पहले भी लौटा दिया जाता है. नियम के अनुसार, कर्मचारी जितना पैसा जमा करते हैं, उतना ही पैसा उसके नियोक्ताओं को भी कर्मचारी के खाते में जमा करना होता है. इस कोष की राशि को निवेश किया जाता है, कर्मचारियों को ब्याज मिलता है. कानूनी तौर पर किसी भी ऐसे कार्यालय या व्यवसाय को पीएफ की व्यवस्था का पालन करना होता है जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों. देश में अभी छह करोड़ से ज्यादा कर्मचारी पीएफ योजना से जुड़े हैं. आज के समय में लोगों के पास निवेश के बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं. लेकिन पीएफ को एक फायदेमंद, लोकप्रिय, विश्वसनीय और सुरक्षित निवेश समझा जाता है, क्योंकि एक तो इसमें बैंक आदि से ज्यादा ब्याज मिलता है, वहीं सरकार के जुड़े होने से गड़बड़ी की आशंका कम रहती है. लेकिन पिछले कुछ समय से पीएफ को लेकर गाहे-बगाहे चिंता के भी स्वर सुनाई देते हैं. दरअसल पिछले कई वर्षों से वित्त मंत्रालय पीएफ के ऊंचे ब्याज पर सवाल उठाते हुए इसे आठ प्रतिशत तक घटाने की कोशिश कर रहा है. वर्ष 2021-22 में पीएफ पर ब्याज घटकर 8.1 प्रतिशत रह गया था, जो चार दशकों में सबसे कम था. इसकी तुलना में 1990 से 1999 तक की अवधि में पीएफ पर 12 फीसदी ब्याज मिलता था, जो अब तक का सर्वाधिक दर था. हर कर्मचारी पीएफ पर ब्याज दर में वृद्धि की उम्मीद लगाये रहता है. इससे उसके भविष्य के सपने जुड़े होते हैं.

अमेरिका -यूरोप की फ्रिक छोड, ऑल टाइम हाई पर पहुंचा रूसी तेल आयात

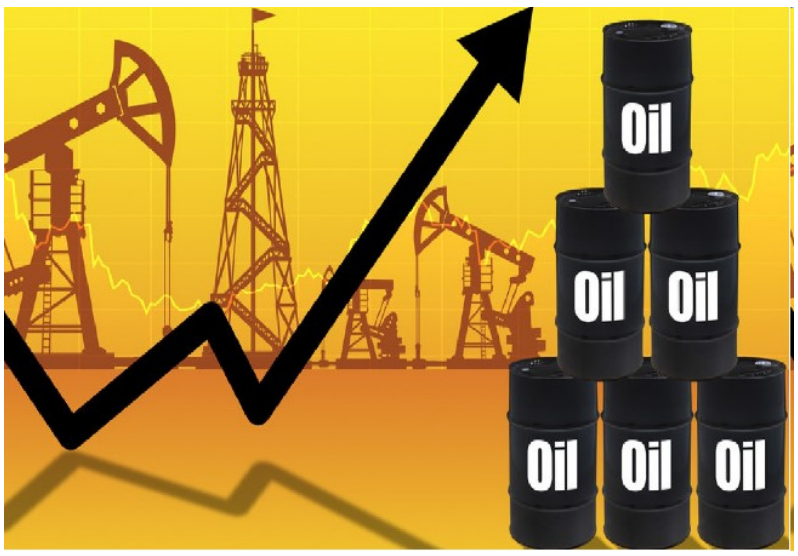

नई दिल्ली । एजेंसी

ना अमेरिका का डर है और ना यूरोप का, भारत रूस से जमकर तेल खरीद रहा है। रूस से भारत का तेल आयात जून में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, आयात में वृद्धि अक्टूबर 2022 के बाद से सबसे धीमी थी। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि भारत का रूसी तेल आयात पीक पर पहुंच गया है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में टैंकर डेटा का हवाला देते हुए यह बात कही। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर व्यापार प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके बाद रूस ने डिस्काउंट पर तेल बेचना शुरू किया था। तब से भारतीय रिफाइनरीज रूसी तेल की भारी खरीद कर रही हैं। हालांकि, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में गिरावट के अभी कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं।

अब कम हुआ रूसी तेल पर डिस्काउंट

हालांकि, अब रूसी तेल पर डिस्काउंट कम हो गया है और पेमेंट सेटलमेंट में समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसने हाल ही में भारतीय रिफाइनरीज को मिडिल ईस्ट के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश के लिए मजबूर कर दिया है।

20 लाख बैरल प्रति दिन की खरीदारी

भारत ने जून में रूसी कच्चे तेल की लगभग 20 लाख बैरल प्रति दिन (बीपीडी) की खरीदारी की थी। आंकड़ों से पता चलता है कि मई से इसमें मामूली वृद्धि हुई है। यूक्रेन युद्ध से पहले, उच्च माल ढुलाई लागत के कारण भारत शायद ही कभी रूस से तेल खरीदता था। जून में भारत ने जितना तेल संयुक्त रूप से इराक और सऊदी अरब से खरीदा, उउससे ज्यादा रूस से आयात किया था। इराक और सऊदी अरब भारत के लिए दूसरे और तीसे सबसे बड़े तेल विक्रेता हैं।

UAE को पीछे छोड़ चौथे नंबर पर आया अमेरिका

आंकड़ों से पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के लिए चौथे सबसे बड़े सप्लायर के रूप में उभरा है, जिसने संयुक्त अरब अमीरात को पांचवें स्थान पर धकेल दिया। बाजार हिस्सेदारी के मामले में, रूस ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल-जून में भारत के कच्चे तेल के आयात का लगभग 42% सप्लाई किया। जबकि मिडिल ईस्ट की हिस्सेदारी पिछले तीन महीनों में फिसलने के बाद बढ़कर लगभग 41% हो गई।

34% गिर गया मिडिल ईस्ट से आयात

जून तिमाही में मिडिल ईस्ट से आयात एक साल पहले की तुलना में लगभग 34% गिर गया। जबकि C.I.S देश- अजरबैजान, कजाकिस्तान और रूस से लगभग तिगुना हो गया। मिडिल ईस्ट से कम आयात ने भारत के समग्र कच्चे तेल के आयात में ओपेक की हिस्सेदारी को कम कर दिया है।

आरबीआई ने बैंक ग्राहकों को दिया बड़ा झटका

अब नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक खाते से निकाल पाएंगे सिर्फ 50 हजार

नई दिल्ली। एजेंसी

रिजर्व बैंक की तरफ से समय-समय पर बैंकों को लेकर नए नियम बनाए जाते हैं और इसके साथ ही इनको कई तरह के निर्देश भी दिए जाते हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक और बैंक को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने को-ऑपरेटिव बैंक से पैसे निकालने की लिमिट को तय कर दिया है यानी अगर आपका इस बैंक में खाता है तो आप सिर्फ 50,000 रुपये निकाल सकते हैं यानी इस बैंक में खाता रखने वाले ग्राहक पचास हजार से ज्यादा की रकम अकाउंट से नहीं निकाल पाएंगे।

इसके साथ ही बैंक कोई भी नया लोन जारी नहीं कर सकता है और न ही बिना केंद्रीय बैंक की परमिशन के फ्रेश डिपॉजिट स्वीकार करेगा। आरबीआई ने नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक पर 24 जुलाई 2023, को कारोबार बंद होने से लेकर के 6 महीने तक की अवधि के लिए व्यवसायिक प्रतिबंध लगाए हैं। रिजर्व बैंक की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, बैंक के जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत 'डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन' में 5 लाख रुपए का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक परिस्थितियों के मुताबिक, अपने फैसले में बदलाव कर सकता है. इसके साथ ही इस फैसले पर विचार कर सकता है. मई में कुछ नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए इस बैंक पर जुर्माना लगाया था। रिजर्व बैंक ने कहा है कि लोन देने वाले बचत बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस में कमी के लिए सीमा के अनुपात के बजाय निश्चित दंडात्मक शुल्क वसूल रहा था। इसी के चलते RBI ने जुर्माने की कार्रवाई की थी।

भारत की GDP को लगेंगे पंख

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष की संभावना से बढ़ी उम्मीद

नई दिल्ली। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर यानी जीडीपी को लेकर बड़ी बात कही है. आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक, इस साल भारत की आर्थिक वृद्धि दर के 6.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह अप्रैल में जताये गये अनुमान के मुकाबले 0.2 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, आईएमएफ ने लगातार चुनौतियों के बारे में भी आगाह किया जो मध्यम अवधि के दृष्टिकोण को कमजोर कर सकती हैं।

आईएमएफ ने कहा कि ताजा अनुमान मजबूत घरेलू निवेश के परिणामस्वरूप 2022 की चौथी तिमाही में उम्मीद से कहीं बेहतर आर्थिक वृद्धि की गति आगे भी जारी रहने का संकेत देता है। आईएमएफ ने अपने ताजा विश्व आर्थिक परिदृश्य में कहा, ''भारत की वृद्धि दर 2023 में 6.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह अप्रैल में जताये गये अनुमान से 0.2 प्रतिशत अधिक है।

रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि वैश्विक स्तर पर वृद्धि दर 2022 के 3.5 प्रतिशत के अनुमान के मुकाबले 2023 और 2024 में कम होकर तीन प्रतिशत रहने की संभावना है. हालांकि, 2023 के लिये अनुमान इस साल अप्रैल में जताये गये अनुमान से कुछ बेहतर है लेकिन ऐतिहासिक मानदंडों के आधार पर वृद्धि दर कमजोर बनी हुई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिये केंद्रीय बैंक के नीतिगत दर में वृद्धि से आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा है। वैश्विक स्तर पर खुदरा मुद्रास्फीति 2022 के 8.7 प्रतिशत से घटकर 2023 में 6.8 प्रतिशत और 2024 में 5.2 प्रतिशत पर आने की संभावना है। मुद्राकोष ने कहा कि अमेरिका में कर्ज सीमा को लेकर गतिरोध के हाल में समाधान और इस साल की शुरुआत में अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड में कुछ बैंकों के विफल होने के बाद उद्योग में उथल-पुथल रोकने के लिये अधिकारियों के कड़े कदम से वित्तीय क्षेत्र में उतार-चढ़ाव का जोखिम कम हुआ है। इससे परिदृश्य को लेकर जोखिम कुछ कम हुआ है। हालांकि, वैश्विक वृद्धि को लेकर जोखिम अभी बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर और झटके आते हैं, तो मुद्रास्फीति ऊंची बनी रह सकती है और यहां तक कि बढ़ भी सकती है। इसमें यूक्रेन में युद्ध तेज होने और मौसम से जुड़ी चुनौतियों के कारण सख्त मौद्रिक नीति रुख शामिल है।

इसमें कहा गया है केंद्रीय बैंक के मौद्रिक नीति को आगे और कड़ा किये जाने से वित्तीय क्षेत्र में कुछ समस्या हो सकती है। चीन में रियल एस्टेट क्षेत्र में समस्या के कारण पुनरुद्धार की गति धीमी हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, ''सरकारी स्तर पर कर्ज संकट कई अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकता है। अच्छी बात यह है कि मुद्रास्फीति उम्मीद से अधिक तेजी से नीचे आ सकती है। इससे कड़ी मौद्रिक नीति की जरूरत नहीं होगी और घरेलू मांग और ज्यादा मजबूत हो सकती है।''

चैटजीपीटी डाउनलोड कर सकते है एंड्रॉइड यूजर्स, ओपनएआई ने की घोषणा

सैन फ्रांसिस्को। एजेंसी

ओपनएआई ने घोषणा की है कि अन्य देशों के साथ अब भारतीय यूजर्स भी अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) चैटबॉट चैटजीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं। कंपनी ने मंगलवार को ट्वीट किया, 'एंड्रॉइड के लिए चैटजीपीटी अब अमेरिका, भारत, बांग्लादेश और ब्राजील में डाउनलोड के लिए उपलब्ध है! हम अगले सप्ताह अतिरिक्त देशों में रोलआउट का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं।'

गूगल प्ले स्टोर पर ऐप के विवरण के अनुसार, एंड्राइड के लिए चैटजीपीटी आपकी हिस्ट्री को सभी डिवाइसों में सिंक करता है, और आपके लिए ओपनएआई से लेटेस्ट मॉडल लाता है। पिछले हफ्ते, ओपनएआई ने चैटजीपीटी के लिए एक नया 'कस्टमाइज इंस्ट्रक्शन' फीचर पेश किया था, जो यूजर्स को एआई चैटबॉट के साथ कुछ भी शेयर करने की अनुमति देता है।

'कस्टमाइज इंस्ट्रक्शन' फीचर वर्तमान में प्लस यूजर्स के लिए बीटा में उपलब्ध है, और कंपनी जल्द ही इस फीचर को सभी यूजर्स के लिए पेश करने की योजना बना रही है। यूजर्स नई बातचीत के लिए किसी भी समय 'कस्टमाइज इंस्ट्रक्शन' को एडिट या डिलीट सकते हैं। इसके अलावा, यूजर्स के इंस्ट्रक्शन शेयर लिंक व्यूअर्स के साथ साझा नहीं किए जाएंगे।कंपनी ने बताया कि जब यूजर्स अपने ओपनएआई अकाउंट्स हटाते हैं, तो उस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में उनके अकाउंट से जुड़े कस्टम इंस्ट्रक्शन भी 30 दिनों के भीतर डिलीट कर दिए जाएंगे।

आईओएस पर, यूजर्स चैटजीपीटी अकाउंट सेटिंग्स के कस्टम इंस्ट्रक्शन के तहत फीचर तक एक्सेस कर सकते हैं।वेब पर फीचर तक एक्सेस करने के लिए, अपने नाम पर क्लिक करें, फिर 'कस्टम इंस्ट्रक्शन' चुनें। दोनों फ़ील्ड में इंस्ट्रक्शन दर्ज करें और किस प्रकार की चीज़ें लिखनी हैं, इसके कुछ उदाहरणों के लिए 'शो टिप्स' पर क्लिक करें। उसके बाद, 'सेव' सलेक्ट करें। इस बीच, पिछले महीने, कंपनी ने आईओएस पर चैटजीपीटी एप्लिकेशन को अपडेट किया था, और प्लस प्लान यूजर्स के लिए बिंग इंटीग्रेशन जोड़ा था ओपनएआई ने अपडेट के साथ हिस्ट्री सर्च में भी सुधार किया।

भारत-बांग्लादेश के बीच रुपये में हुआ पहला शिपमेंट

डॉलर की निर्भरता कम करना नए कदम का उद्देश्य

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत ने पहली बार बांग्लादेश के साथ रुपये में व्यापार किया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना स्थित पेट्रापोल सीमा से बांग्लादेश के लिए पहला रुपया व्यापार शिपमेंट मंगलवार को किया गया। भारत सरकार रुपये से व्यापार को बढ़ावा दे रही है। इसका उद्देश्य डॉलर से निर्भरता को कम करने के साथ-साथ क्षेत्रीय मुद्रा को मजबूत करना है।

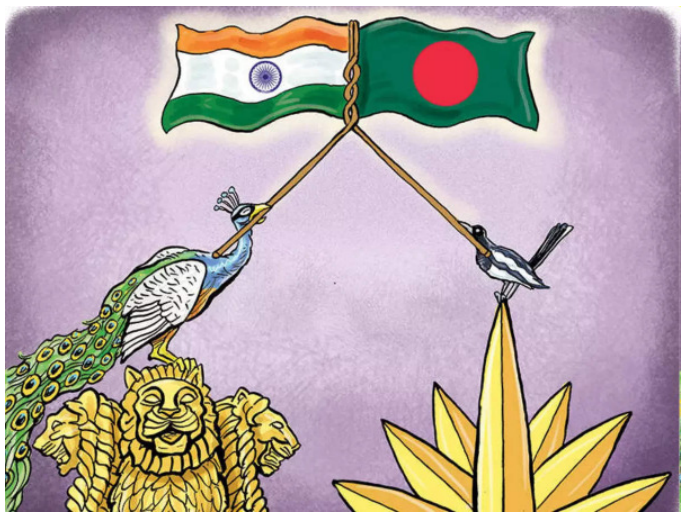

नोस्ट्रो खाते खोलने की अनुमति

लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आईसीपी पेट्रापोल) के प्रबंधक कमलेश सैनी का कहना है कि शिपमेंट टाटा मोटर्स से वाहन चेसिस का था, जिसका मूल्य 1.23 करोड़ रुपये है। शिपमेंट भारतीय रुपये में किया गया है। इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। भारत और बांग्लादेश में बैंकों को अनुमति दी गई है कि नोस्ट्रो खाते खोल सकते हैं। बता दें, नोस्ट्रो खाते का उद्देश्य विदेशी मुद्रा लेनदेन से जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य है कि दूसरे देश के बैंक में एक खाता।

बांग्लादेश गवर्नर- महान यात्रा का पहला कदम

बांग्लादेश बैंक के गवर्नर अब्दुर रूप तालुकदार ने बताया कि जुलाई की शुरुआत में ढाका में रुपया व्यापार लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तालुकदार ने रुपये के साथ व्यापर की शुरुआत को एक महान यात्रा का पहला कदम बताया है। टका-रुपया दोहरी मुद्रा कार्ड की शुरुआत के बाद से भारत के साथ व्यापार लेनदेन की लागत कम हो जाएगी। कार्ड योजना सितंबर से शुरू होगा। बांलादेश का आयात भारत से 13.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। वहीं बांगलादेश का निर्यात दो बिलियन अमेरिकी डॉलर का है।

क्या बढ़ेगी 2000 के नोट बदलने की आखिरी तारीख

500 के नोट बंद करने और 1000 के नए नोट जारी करने पर भी सवाल

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्र सरकार की ओर से 2000 के नोट की आखिरी डेडलाइन बढ़ाने को लेकर संसद में जानकारी दी गई है। केंद्रीय

बैंक आईबीआई की ओर से 2000 के नोट बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक की गई है। जिन लोगों के पास भी 2000 के नोट मौजूद है, वे इस तारीख तक किसी भी बैंक में जाकर नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं।

कुछ सांसदों की ओर से 2000 का नोट बदलने की डेडलाइन को आगे बढ़ाने को लेकर सरकार से सवाल किया गया था। इसके जबाव में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा कि 2000 का नोट बदलने की आखिरी तारीख में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि 2000 का नोट बदलने के लिए पहले से तय आखिरी तारीख 30 सितंबर नहीं बदलने वाली है। इसके साथ ही बताया गया कि सरकार के पास मौजूदा 2000 के नोट को बदलने के लिए पर्याप्त मात्रा में दूसरी वैल्यू के नोट मौजूद हैं।

आरबीआई की ओर से 19 मई को 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा था कि 2000 के नोट करेंसी के रूप में वैध रहेंगे। साथ ही कहा कि बैंक की ओर से ये फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया गया था। आरबीआई की ओर से जून में जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि नोट वापस लिए जाने के एक महीने में करीब 72 प्रतिशत नोट बदले या फिर जमा हो चुके हैं। आरबीआई के मुताबिक, कोई भी एक बार में अधिकतम 2000 रुपये या दो-दो हजार के दस नोटों को बदल सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार के दस्तावेज और आईडी की जरूरत नहीं होगी।

500 रुपये के नोट को क्या वापस ले रही सरकार?

संसद के मॉनसून सत्र में 500 रुपये के बंद हो जाने की खबरों पर वित्त मंत्रालय से सवाल पूछा गया। इसके साथ ही 1,000 रुपये के नोटों को दोबारा शुरू करने के बारे में भी सवाल पूछा गया।इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उन सभी खबरों का खंडन किया जिसमें ये दावा किया जा रहा कि सरकार ने 500 रुपये के नोट को बंद करके 1,000 रुपये के नोट को दोबारा शुरू करने जा रही है। उन्होंने इन सभी खबरों को गलत बताते हुए बताया है सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है। इस मामले पर लिखित जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने जानकारी दी है कि सरकार ने 2,000 रुपये के नोटों को चरणबद्ध तरीके से मार्केट से हटाया है। इसके साथ ही सरकार ने इसके बदले 500 रुपये के नोटों की पर्याप्त मात्रा में बफर स्टॉक रखा है।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 15 महीने के टॉप पर

नई दिल्ली। एजेंसी

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 15 महीने के हाई पर पहुंच गया है। 14 जुलाई को समाप्त सप्ताह में यह 12.74 अरब डॉलर बढ़कर 609.02 अरब डॉलर हो गया। आरबीआई आरबीआई ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे पिछले सप्ताह देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 1.23 अरब डॉलर बढ़कर 596.28 अरब डॉलर रहा था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार अक्टूबर, 2021 में 645 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। लेकिन वैश्विक घटनाओं के कारण पैदा हुए दबावों के बीच रुपये को संभालने के लिए मुद्रा भंडार का उपयोग करने से इसमें गिरावट आई। इस बीच पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी डबल हो गया है।

रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार, 14 जुलाई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा फॉरेन करेंसी एसेट्स 11.19 अरब डॉलर बढ़कर 540.17 अरब डॉलर हो गईं। डॉलर में एक्सप्रेस की जाने वाली फॉरेन करेंसी एसेट्स में यूरो, पौंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं में आई घट-बढ़ के प्रभावों को भी शामिल किया जाता है। रिजर्व बैंक के अनुसार स्वर्ण भंडार का मूल्य 1.14 अरब डॉलर बढ़कर 45.19 अरब डॉलर हो गया। आंकड़ों के अनुसार, एसडीआर 25 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.48 अरब डॉलर हो गया। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के पास रखा देश का मुद्रा भंडार 15.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 5.17 अरब डॉलर हो गया।

पाकिस्तान का डबल

इस बीच पड़ोसी देश पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी 14 जुलाई को खत्म हफ्ते में करीब दोगुना होकर 8.73 अरब डॉलर पहुंच गया। आईएमएफ, सऊदी अरब और यूएई से मिली मदद के दम पर पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल आई है। यह पिछले साल अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा है। तब पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के पास 8.76 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था। पाकिस्तान को पिछले हफ्ते करीब 4.2 अरब डॉलर की मदद मिली। पिछले एक साल में पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट में 13 परसेंट और एफडीआई में 25 परसेंट गिरावट आई है। पाकिस्तान के पुराने दोस्त चीन ने उसे 60 करोड़ डॉलर का कमर्शियल लोन दिया है।

डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे की गिरावट के साथ खुला

नई दिल्ली। एजेंसी

डॉलर के मुकाबले रुपया बुधवार को 7 पैसे की गिरावट के साथ 81.95 के स्तर पर है। कारोबारी सत्र में अमेरिकी मुद्रा में तेजी देखी जा रही है। इसके पीछे की वजह अमेरिकी फेड की ओर से बैठक में ब्याज दर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही कच्चे तेल में तेजी होने के कारण रुपये पर दबाव बना हुआ है। कच्चे तेल की कीमत 83 डॉलर प्रति बैरल के करीब बनी हुई है।

फॉरेक्स ट्रेडर्स का कहना है कि फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर आज कोई एलान हो सकता है। इस कारण निवेशक अभी सतर्क बने हुए हैं। घरेलू बाजार मजबूत होने के चलते गिरावट सीमित है।

डॉलर के मुकाबले रुपये में शुरुआती कारोबार

इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज के मुताबिक, रुपया 81.89 पर खुला और इस दौरान रुपये ने 81.87 के उच्चतम स्तर और 81.96 के न्यूनतम स्तर को छुआ और 81.95 के स्तर पर आ गया। इस तरह रुपये में 7 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 81.88 के स्तर पर बंद हुआ है।अमेरिकी मुद्रा की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.01 प्रतिशत गिरकर 101.34 पर आ गया है। डॉलर इंडस्क दुनिया की छह बड़ी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति को दर्शाता है।

भारतीय बाजारों में तेजी

जानकारी के अनुसार 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 317.49 अंक या 0.48 प्रतिशत बढ़कर 66,673.20 पर कारोबार कर रहा था। एनएसई निफ्टी 79.20 अंक या 0.40 प्रतिशत बढ़कर 19,759.80 पर था। एक्सचेंज डाटा के मुताबिक, एफआईआई की ओर से मंगलवार को 1088.76 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे गए थे।

महाराजा को 'टाटा' कहेगी एयर इंडिया

छूट जाएगा 77 साल पुराना नाता

नई दिल्ली। एजेंसी

एयर इंडिया कभी दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन्स में से एक थी। इसकी ब्रांडिंग महाराजा के इर्दगिर्द बुनी गई थी। लंबी मूंछ वाले महाराजा 77 साल के एयर इंडिया का पर्याय बने हुए हैं। जेआरडी टाटा (ब्ंः ऊ्ँ) के जमाने में बॉबी कूका ने महाराजा को चमकाया था। वह कंपनी के कमर्शियल डायरेक्टर थे और उन्होंने ही महाराजा के तौर पर एयर इंडिया की ब्रांडिंग की थी। अब करीब सात दशक बाद जब एयर इंडिया की टाटा ग्रुप में वापसी हुई है और एक बार फिर इसकी ब्रांडिंग पर काम चल रहा है। लेकिन एयर इंडिया अब मस्कट के तौर पर महाराजा को टाटा कहने की तैयारी में है। अब महाराजा दूसरी भूमिका में दिख सकता है। टाटा ग्रुप ने पिछले साल जनवरी में एयर इंडिया को खरीदा था और तभी से इसे फिर से चमकाने की रणनीति पर काम चल रहा है।

सूत्रों के अनुसार एयर इंडिया देश में आम लोगों की पसंदीदा एयरलाइन बनना चाहती है। इसके यात्रियों में बिजनस और कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स भी बड़ी संख्या होगी। पगड़ी पहनने वाले और बड़ी मूछों वाले महाराजा की अपनी सफल कहानी रही है। लेकिन वह आज के जमाने के कस्टमर्स से मेल नहीं खाता है। आज के जमाने में किसी भी ग्लोबल एयरलाइन के पास कोई मस्कट नहीं है। लेकिन एयरपोर्ट्स पर लाउंज और बिजनस क्लास कैबिन्स में इसके नाम का इस्तेमाल जारी रखा जा सकता है। लंदन की ब्रांडिंग एंड डिजाइन कंसल्टेंसी फर्म फ्यूचरब्रांड को एयर इंडिया की ब्रांडिंग स्ट्रैटजी बनाने का काम दिया गया है।

ब्रांड चमकाने की जिम्मेदारी

फ्यूचरब्रांड ने अमेरिकन एयरलाइंस और ब्रिटेन की लग्जरी ऑटो कंपनी बेंटले के साथ-साथ 2012 के लंदन ओलंपिक की ब्रांडिंग की थी। एयर इंडिया का मुकाबला एमिरेट्स और सिंगापुर एयरलाइन्स जैसी एलीट कंपनियों से है। अगस्त में टाटा की नई ब्रांड आइंटिटी लॉन्च की जाएगी। एडवरटाइजिंग और मार्केटिंग का काम प्रसून जोशी की अगुवाई वाली कंपनी मैककैन वर्ल्डग्रुप इंडिया को दिया गया है। टाटा संस और एयर इंडिया ने इस बारे में भेजे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। एयर इंडिया साथ ही कलर स्कीम में भी बदलाव कर रही है। अभी एयरलाइन की पहचान लाल और सफेद रंग है लेकिन अब इमें डार्क पर्पल भी शामिल किया जा रहा है। पर्पल विस्तारा का कलर है जिसका मार्च 2024 में एयर इंडिया में विलय होने जा रहा है।

टाटा के इस प्रीमियम ब्रांड की पहचान को बनाए रखने के लिए एयर इंडिया में पर्पल कलर का समावेश किया जा रहा है। नई कलर स्कीम को एयरबस ए350 में लॉन्च किया जाएगा जिसका नवंबर में एयर इंडिया के बेड़े में शामिल करने की योजना है। विस्तारा को एयर इंडिया में मर्ज करके एक सिंगल फुल सर्विस एयरलाइन बनाई जाएगी। सूत्र ने कहा कि विस्तारा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है लेकिन भारत से बाहर इसे कम ही लोग जानते हैं। इसलिए विमान की टेल और इंजन पर इसका कलर बना रहेगा। एयर इंडिया ग्रुप में लो-कॉस्ट एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस भी शामिल है। कंपनी फ्लाइट सेफ्टी और कस्टमर सर्विस के लिए विस्तारा के एसओपी को अपना सकती है।

लॉन्च होते ही सहारा पोर्टल पर 7 लाख रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली। एजेंसी

सहारा के स्कीमों में फंसे निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के लिए सरकार ने सहारा पोर्ट्ल की शुरुआत की। गृहमंत्री अमित शाह ने सहारा पोर्टल की शुरुआत की। लॉन्च होते ही इस पोर्टल पर 7 लाख रजिस्ट्रेशन कर दिए गए। अब तक 158 लाख रुपये के लिए सहारा निवेशकों की ओर से आवेदन किया जा चुका है। सरकार की ओर से लॉन्च किए गए इस पोर्टल के जरिए सिर्फ चार सोसाइटी के लोगों का पैसा वापस किया जाएगा। आवेदन के 45 दिन बाद सरकार लोगों के खाते में पैसा जमा कर देगी। फिलहाल रिफंड के लिए 10000 रुपये की कैंपिंग है। अगर आपका भी पैसा सहारा में फंसा है और आपने अब तक रिफंड पोर्टल के जरिए आवेदन नहीं किया है तो बिना देर किए फौरन करें। बिना रजिस्ट्रेशन के आप सहारा स्कीम में फंसा अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे में आपको रिफंड पाने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के 45 दिनों के भीतर लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस रिफंड के लिए अब तक 7 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जिसमें से सिर्फ 2 लाख 84 हजार डिपॉजिटर्स ने आधार वेरिफिकेशन किया है। जबकि 18,442 ने सहारा सहकारी समितियों को भुगतान करने की रसीद अपलोड की है। जिन लोगों ने सभी डिटेल जमा करने के बाद वेरिफाई किया है, वो सहारा में फंसा अपना पैसा पाने के हकदार बन चुके हैं।

फिलहाल 10 हजार की कैंपिंग

सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में जिन लोगों का पैसा फंसा है, उन्हें पूरा रिफंड ब्याज समेत मिलेगा, लेकिन पहले चरण में सरकार ट्राइल के तौर पर लोगों को 10 हजार रुपये अकाउंट में डालेगी। इस पोर्टल के जरिए सरकार सहारा के 10 करोड़ लोगों को कुल 5000 करोड़ रुपये वापस करेगी। हर जमाकर्ता को फिलहाल अधिकतम 10 रुपये ही रिफंड किए जाएंगे। ये सिर्फ ट्रायल के तौर पर किया जा रहा है। जैसे ही ट्रायल सफल हो जाएगा, निवेशकों को उनका बाकी पैसा ब्याज समेत वापस कर दिया जाएगा।

5 साल बाद भारत में नहीं होगा पेट्रोल का इस्तेमाल

कम कीमत पर चलेंगी गाड़ियां

एजेंसी

बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों से परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर है। देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कई बार पेट्रोल डीजल से देश को मुक्त कराने की बात कह चुके हैं। गडकरी ने आगामी दिनों में हरित ईंधन इस्तेमाल होने का विश्वास दिलाया है। नितिन गडकरी कई बार कह चुके हैं कि आने वाले 5 सालों में कार और स्कूटर पूर्णरूप से हाइड्रोजन, एथेनॉल, सीएनजी या एलएनजी पर आधारित होंगे। इससे पहले गडकरी फ्लेक्स फ्यूल यानी वैकल्पिक ईंधन वाले वाहन लाने पर जोर दे चुके हैं। पिछले दिनों गडकरी ने कार निर्माताओं से देश में फ्लेक्स इंजन के उत्पादन को प्राथमिकता देने को कहा था। गडकरी के मुताबिक, अब देश में इथेनॉल आसानी से उपलब्ध है। देश में 70 फीसदी पेट्रोल की खपत दोपहिया वाहनों से होती है। इसलिए, फ्लेक्स ईंधन वाहनों के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करने की आवश्यकता है।फ्लेक्स इंजन वाली कार इथेनॉल के साथ गैसोलीन और मेथनॉल के साथ गैसोलीन का उपयोग कर सकती है। इसमें इंजन इसे अपने हिसाब से डिजाइन करता है। फिलहाल इसमें ज्यादातर इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी कारें ब्राजील, अमेरिका, कनाडा और यूरोप में खूब चलती हैं।

क्या होगा हाइड्रोजन ईंधन का स्रोत ?

पेट्रोल के विपरीत, हाइड्रोजन ईंधन का कोई भंडार नहीं है। यह प्राकृतिक गैस या बायोमास को विखंडित करके या पानी के माध्यम से बनाया जाता है। आइसलैंड में हाइड्रोजन उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है।

हाइड्रोजन फ्यूल के कई फायदे

हाइड्रोजन ईंधन अधिक कुशल है क्योंकि यह रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल कारों में पारंपरिक ईंधन कारों की तुलना में उत्सर्जन का स्तर काफी कम और स्वच्छ होता है। एक सामान्य इलेक्ट्रिक कार में बैटरी चार्ज करने में कई घंटे लगते हैं। लेकिन हाइड्रोजन 5 से 7 मिनट में भर जाता है। यह काफी अच्छी रेंज भी देता है। हाइड्रोजन ईंधन का एक पूरा टैंक 650 किमी तक की यात्रा कर सकता है। इसे पूरी तरह से शून्य उत्सर्जन वाली कार कहा जा सकता है क्योंकि उत्सर्जन में सिर्फ पानी निकलता है।

UAE में कोरोना के नए वेरिएंट से मचा हड़कंप, WHO ने की पहचान

पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर लंबे समय तक रहा है। अभी भी इसका खतरा टला नहीं है। अब इस जानलेवा बीमारी का एक नया वेरिएंट सुर्खियों है। यह नया वेरिएंट संयुक्त अरब अमीरात में पाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस नए वेरिएंट की पुष्टि की है। WHO ने 28 साल के एक शख्स पर मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस की पहचान की है। WHO के मुताबिक, मरीज अबू धाबी के अल ऐन शहर का रहने वाला है। उसकी कोई ट्रैवेल हिस्ट्री नहीं मिली है। कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट से पीड़ित शख्स ऊंट, बकरियो भेड़ों के साथ कभी संपर्क में नहीं आया है। जिससे यह बीमारी फैलती है। UAE ने 10 जुलाई को विश्व स्वास्थ्य संगठन को सूचित किया था। इसके बाद WHO ने इस नए वेरिएंट की पुष्टि की है।

बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ के चलते मरीज को 8 जून को भर्ती कराया गया था। जहां MERS-COV पॉजिटिव की चपेट में आने की पुष्टि हुई। इस शख्स के कोरोना वायरस के इस वेरिएंट की चपेट में आने का पता लगने के बाद से स्वास्थ्य अधिकारियों की ओर से 108 लोगों की और जांच की गई है। यह सभी वो लोग हैं जोकि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए थे। हालांकि अब तक इस नए वेरिएंट से संक्रमित दूसरा मरीज नहीं मिला है। जिस शख्स में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। उसकी मौजूदा स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है।

बता दें कि MERS-कोरोना वायरस को मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब इस वायरस का कोई मामला सामने आया है। इससे 11 साल पहले यानी साल 2012 में इस वायरस का पहला मामला सऊदी अरब में दर्ज किया गया था। ये वायरस कोरोना से थोड़ा सा अलग है। MERS-Corona Virus में चार संरचनात्मक प्रोटीन पाए जाते हैं जिनके नाम स्पाइक (5), लिफाफा (E), मेम्ब्रेन (M) और न्यूक्लियोकैप्सिड (N) हैं। इनमें से ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन वायरस की सतह पर एक ट्रिमर के रूप में पाया जाता है। जिसमें 51 और 52 सबयूनिट होते हैं।WHO के मुताबिक, इस MERS-Cov की चपेट में अब तक कुल 2,605 लोग आए हैं। जिनमें से 936 की मौत भी हो चुकी है। यह अब तक 27 देशों में फैल चुका है। इस वायरस के सबसे ज्यादा लोग सऊदी अरब में संक्रमित हुए हैं। ड्रोमेडरी ऊंटों के असुरक्षित संपर्क से लोग संक्रमित हुए हैं। बता दें कि ये वायरस एक जूटोनिक वायरस है जो जानवरों से इंसानों में फैल जाता है। इस वायरस के बारे में अभी भी पूरी बातें सामने नहीं आई हैं। MERS-COV से संक्रमित होने पर बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं। हालांकि, जब मरीज को निमोनिया हो जाता है तो उसे सबसे ज्यादा परेशानी होती है। इसके साथ ही इससे पीड़ित मरीज में दस्त के अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के लक्षण भी दिखते हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक, इस वायरस की चपेट में आए हुए मामलों में करीब 35 फीसदी लोगों की मृत्यु हो गई है।

हाईवे-48 पर बनेंगे 4 छोटे जंगल, होने जा रहा अनोखा प्रयोग

9,000 करोड़ की लागत से बन रहा ये प्रोजेक्ट

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश में एक्सप्रेसवे और हाईवे के निर्माण में सरकार यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं देने के मकसद से अनोखे प्रयोग कर रही है। इसी कड़ी में अब नेशनल हाईवे-48 पर हरियाली को बढ़ावा देने के लिए मियावाकी तकनीक के जरिए 4 छोटे जंगल विकसित किए जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने शनिवार को एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के दौरान कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे के शुरू होने से गुरुग्राम और दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) के बीच संपर्क में सुधार होगा. इस परियोजना में सुरंग, अंडरपास, फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर होंगे।

क्या है मियावाकी तकनीक

मियावाकी तकनीक छोटी सी जगह में जंगल उगाने का तरीका है, जिसमें स्थानीय प्रजाति के पौधों पर जोर दिया जाता है। मियावाकी पद्धति वृक्षारोपण की एक जापानी तकनीक है, इसे प्रसिद्ध जापानी वनस्पतिशास्त्री अकीरा मियावाकी ने विकसित किया था। इस विधि का प्रयोग कर के घरों के आसपास खाली पड़े स्थान को छोटे बगानों या जंगलों में बदला जा सकता है। इस पद्धति में पौधों को एक-दूसरे से कम दूरी पर लगाया जाता है।

महिपालपुर से गुरुग्राम स्थित खेड़की दौला को जोड़ने के लिए तैयार किए जा रहे द्वारका एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य आखिरी चरण में है। इस एक्सप्रेस-वे के लिए बजघेड़ा से NH-48 पर बनने वाले क्लोवर लीव पर 4 छोटे जंगल विकसित किए जाएंगे।

मियावाकी तकनीक ने खराब भूमि को बहाल करने, कार्बन को अलग करने, जैव विविधता को बढ़ावा देने और शहरी क्षेत्रों में हरित स्थान बनाने में अपनी प्रभावशीलता के कारण दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की है। इस तकनीक को पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने और विभिन्न देशों में वन क्षेत्र को बढ़ाने और उनके पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए अपनाया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के महिपालपुर को गुरुग्राम में एनएच-48 पर स्थित खेड़की दौला से जोड़ने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे करीब 9,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। इस सड़क का 18.9 किमी हिस्सा हरियाणा में है और 10.1 किमी हिस्सा दिल्ली में है।

मियावाकी तकनीक से उगे जंगल के फायदे

जैव विविधता- इस विधि में एक छोटे से क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की देशी पौधों की प्रजातियों को रोपना शामिल है, जिससे जंगल के भीतर अधिक जैव विविधता सुनिश्चित होती है। यह विविधता एक जटिल और स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की ओर ले जाती है, जो विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती है।

आसपास वृक्षारोपण- इस तकनीक में किसी क्षेत्र में पेड़-पौधे सघन रूप से लगाए जाते हैं, जिससे जंगल जल्दी से स्थापित हो जाते हैं.

बहुस्तरीय वनस्पति- यह तकनीक वनस्पति की विभिन्न परतों के विकास को बढ़ावा देती है, जैसे ऊंचे पेड़, उप-छत वाले पेड़, झाड़ियाँ और जमीन से ढके पौधे आदि।

रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट 11% गिरा

लेकिन 36 लाख इन्वेस्टर्स को मिली खुशखबरी

नई दिल्ली। एजेंसी

मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जून तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए। अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 11 परसेंट गिरकर 16,011 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल समान तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 17,955 करोड़ रुपये रहा था। जून तिमाही में कंपनी के रेवेन्यू में भी 5.3 परसेंट की गिरावट आई है और यह 2.07 लाख करोड़ रुपये रह गया। पिछले साल समान तिमाही में यह 2.19 लाख करोड़ रुपये था। ब्रोकरेज कंपनियों ने रिलायंस का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 10 परसेंट गिरावट के साथ 16,170 करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया था। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू भी सालाना आधार पर दो फीसदी गिरावट के साथ 2.15 लाख रुपये रहने का अनुमान था। लेकिन ये दोनों अनुमान से कम रहे। कंपनी के बोर्ड ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए प्रति शेयर नौ रुपये का डिविडेंड देने की घोषणा की है। इससे कंपनी के 36 लाख से अधिक इन्वेस्टर्स को फायदा होगा। पिछली तिमाही के मुकाबिल रिलायंस के कंसोलिडेटेड टॉपलाइन 2.5 फीसदी गिरा है जबकि बॉटमलाइन में 17 फीसदी गिरावट आई है। ओ2सी बिजनस के कमजोर प्रदर्शन के कारण कंपनी का रेवेन्यू गिरा है। इस सेगमेंट का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले करीब 18 परसेंट गिरकर 1.33 लाख करोड़ रुपये रहा। हालांकि रिटेल और डिजिटल सर्विसेज बिजनस में डबल डिजिट ग्रोथ ने रिलायंस को प्रॉफिट और रेवेन्यू में बड़ी गिरावट से बचा लिया। रिलायंस रिटेल (Reliance Retail) का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 18.8 परसेंट उछलकर 2,448 परसेंट रहा। इस दौरान कंपनी का ग्रॉस रेवेन्यू बी 19 परसेंट की तेजी के साथ 69,948 करोड़ रुपये पहुंच गया जो पिछले साल समान तिमाही में 58,554 करोड़ रुपये था।

जियो का रिजल्ट

इससे पहले रिलायंस की टेलिकॉम कंपनी जियो ने भी अपने जून तिमाही के नतीजों की घोषणा की। कंपनी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 12 फीसदी बढ़कर 4,863 करोड़ रुपये रहा। वहीं, ऑपरेशन से रेवेन्यू 10 फीसदी बढ़कर 24,042 करोड़ रुपये हो गया। पहली तिमाही में रिलायंस जियो का कुल खर्च बढ़कर 17,594 करोड़ रुपये रहा। यह एक साल पहले 16,136 करोड़ रुपये था।

1405 करोड़ में बनकर तैयार है गुजरात का हीरासर ग्रीनफ़ील्ड एयरपोर्ट एयरपोर्ट

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

गुजरात का ग्रीनफ़ील्ड एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। पीएम मोदी 27 जुलाई को इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। 1405 करोड़ की लागत से बना यह एयरपोर्ट जल्द ही खोल दिया जाएगा। 23,000 वर्गमीटर में बने इस एयरपोर्ट पर हर घंटे 1280 यात्रियों के संचालन की क्षमता है। राजकोट से लगभग 30 किलोमीटर दूर, नेशनल हाईवे नंबर 27 के निकट हीरासर ग्रीनफ़ील्ड एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है।

क्या है खास

2534 एकड़ में फैले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27 जुलाई को करने वाले हैं। 3.04 किलोमीटर लंबे और 45 मीटर चौड़े रनवे वाले इस एयरपोर्ट पर एक साथ 14 विमान पार्क किए जा सकते हैं। एयरपोर्ट पर 50,800 वर्ग मीटर में एप्रोन बेय्स बनाया गया है। पैसेंजर टर्मिनल इतना विशाल है कि भीड़भाड़ के समय भी हर घंटे 1280 यात्रियों का संचालन कर सकता है। इस एयरपोर्ट से एयरबस ए-380, बोइंग 747, बोइंग 777 जैसे विमान उड़ान भर और लैंड कर सकेंगे। एयरपोर्ट पर सोलर पावर सिस्टम, ग्रीन बेल्ट , रेन वॉटर हार्वेस्टिंग जैसी सुविधाएं हैं। एयरपोर्ट पर भीड़ का नियंत्रित करने के लिए 12 चेकइन प्वाइंट की व्यवस्था है। चार पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज, तीन कन्वेयर बेल्ट और 8 चेक-इन काउंटर्स शामिल हैं। भविष्य में अन्य 12 चेक-इन काउंटर्स बनाए जाएंगे।

पीएफ पर अब 8.15% ब्याज

ईपीएफ खाताधारक घर बैठे चेक करें खाते का बैलेंस

नई दिल्ली । एजेंसी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों खाताधारकों को बड़ा तोहफा देते हुए ईपीएफ ब्याज दर की घोषणा कर दी है। अब ईपीएफ खाताधारकों को 8.15 फीसदी ब्याज दर मिलेगा। पिछली बार ईपीएफओ ने मार्च 2023 में ईपीएफ ब्याज दर बढ़ाई थी। ईपीएफओ खाताधारक अब घर बैठे पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया काफी आसान हो गई है।

म्यूचुअल फंड के जरिए पाएं आर्थिक मजबूती, निवेश की शुरुआत करें

ईपीएफओ पीएफ खाताधारकों की जमा राशि को कई जगहों पर निवेश करता है। इस निवेश से होने वाली कमाई का एक हिस्सा ब्याज के रूप में खाताधारकों को दिया जाता है। ईपीएफओ के सर्कुलर के अनुसार ईपीएफ योजना के प्रत्येक सदस्य के खाते में वर्ष 2022-23 के लिए 8.15% की दर से ब्याज जमा किया जाएगा। हालांकि, पिछली बार मार्च में 8.15 फीसदी ब्याज दर की घोषणा की गई थी, जुलाई में भी यही ब्याज दर लागू रखी गई है।

कर्मचारी भविष्य निधि वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य योगदान है। नियोक्ता भी ईपीएफ खाते में समान योगदान करने के लिए बाध्य है। मासिक आधार पर एक कर्मचारी अपनी कमाई का 12% अपने ईपीएफ खाते में योगदान करता है। कर्मचारी का पूरा योगदान ईपीएफ खाते में डाला जाता है। जबकि, नियोक्ता के मामले में ईपीएफ खाते में केवल 3.67 प्रतिशत जमा किया जाता है, शेष 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है।

ईपीएफ खाता में मौजूद राशि 4 तरीके से जांच की जा सकती है।

उमंग ऐप का उपयोग करके

ईपीएफ सदस्य ई-सेवा पोर्टल पर जाकर

ईपीएफओ के टोलफ्री नंबर मिस्ड कॉल देकर

ईपीएफओ के नंबर पर एसएमएस भेजकर

तारे बताते हैं बीमारी

डॉ. संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

शास्त्रों के अनुसार मानव जीवन में होने वाले कष्ट तीन प्रकार के होते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक। ज्योतिष शास्त्र से मानव जीवन में होने वाले दैहिक प्रकोपों यानि शारीरिक कष्टों, बीमारियों आदि के कारणों और निवारणों को जाना जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक राशि और उनके ग्रह मानव शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रभाव डालते हैं। अथवा यू कहें कि अपना अधिपत्य रखते हैं। उदाहरण के लिए मेष राशि- मस्तष्क, वृषभ- मुख, मिथुन-छाती, कफ, श्वास, कर्क- ह्दय, सिंह- पेट,गर्भाशय, कन्या- कमर, तुला- मूत्राशय, वृश्चिक- गुदा-लिंग, धनु- पुट्ठे, मकर-घुटने, कुंभ-जंघा और मीन राशि पैरों पर असर रखती है।

इसी प्रकार ग्रहों में सूर्य-चंद्र मानव शरीर में नेत्रों के कारक हैं। मंगल रक्त और पुट्ठों, बुध त्वचा और श्वांस, गुरू शरीर में रिक्त स्थान, शुक्र 'शरीर में द्रव्य, वीर्य, रज आदि का कारक है। शनि स्त्रायु, नाड़ी तंत्र, राहू-केतु वायु, अग्नि आदि के कारक माने जाते हैं।

कुंडली में इस प्रकार के कारक राशियों व ग्रहों के अच्छे तालमेल से व्यक्ति के शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों को निरोगता और पुष्टता परिलक्षित होती है। कारक राशियों व ग्रहों की आपस में शत्रुता व निचस्थता के रहते विभिन्न बीमारियों की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे द्वितीय भाव में स्थित राशि पर नीच है और 'शत्रु राशि के प्रभाव से व्यक्ति के मुख संबंधी रोगों की जानकारी मिलती है। तृतीय भाव के बिगड़ने पर व्यक्ति को हृदय और चतुर्थ भाव खराब होने पर पेट संबंधी रोग होने की जानकारी मिलती है। सप्तम या सप्तमेश का शुक्र अथवा गुरू नीचस्थ होने पर शुगर, पंचम या पंचमेश पाप ग्रहों से पीड़ित होने पर सिरदर्द, पेट दर्द, संतानोत्पत्ति बाधक योग बनते हैं। सप्तम व सप्तमेश व शुक्र आदि जैसे क्रूरुर ग्रहों से पीड़ित होना गुप्तागों संबंधी बीमारियों का द्योतक है। द्वादशस्थ सूर्य अपेंडीसाइटिस, व छठे भाव में नीच का सूर्य होने से किडनी से संबंधित रोग होने का संकेत मिलता है। सूर्य-चंद्र पाप ग्रहों से पीड़ित हों अथवा नीच राशिस्थ हो अथवा द्वादश भावों पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि होने से व्यक्ति नेत्र रोगों से पीड़ित होता है। इसी प्रकार मंगल नीचस्थ राहू की युति व्यक्ति की कुंडली में जिस भाव में होगी, उस भाव से संबंधित अंग में कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। उक्त बीमारियों संबंधित भावों के राशि अधिपतियों और उन्हें प्रभावित करने वाले ग्रहों की महादशा व अंतरदशाओं के समयकाल में दृष्टिगोचर होती है।

ज्योतिष की ज्योति में हम समय से पूर्व ही बीमारियों की रोकथाम के उपाय कर सकते हैं। जरूरी चिकित्सीय परामर्श व सावधानियां बरत कर सुरक्षित जीवन जी सकते हैं।

जानें क्या है शिव लिंग का रहस्य? शिवजी के बिना हर पूजा है अधूरी

डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
इंदौर (म.प्र.)

आशुतोष शिवजी जन गण के देव हैं. कहीं मनुष्य की आकृति के रूप में तो कहीं मंदिरों के भीतर बाहर या बाग बगीचों में विराजमान दिख जाते हैं. लिंग के रूप में भी बाबा प्राचीन से नवीनतम मंदिर, नदी किनारे, पेड़ के नीचे, खेत-खलिहान या फिर गली के नुक्कड़ में दिखते रहते हैं. उनको जन गण मन का देवता कहा जाता है. सबके लिए सरल, सुगम, सुलभ दर्शन होने और जो भी मिले उसी वस्तु को फिर वह चाहे एक पत्ता, फूल, फल या अंजुली या लोटा भर जल ही क्यों न हो, अर्पण करने से वह खुश हो जाते हैं. आशुतोष नाम भी इसलिए है, क्योंकि आशुतोष अर्थात शीघ्रता से संतुष्ट होने वाले देव.

शिवलिंग का रहस्य

लिंग शब्द का अर्थ है, जिसमें सबकुछ लीन हो जाए. इसका अर्थ है- बीज, सूक्ष्म या नैनो पार्टिकल, चिह्न, निशानी, प्रतीक आदि. अतः अनंत, शून्य, आकाश, ब्रह्मांड का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है. स्कंद पुराण के अनुसार, अनंत आकाश स्वयं ही लिंग है. धरती उसकी पीठ है. सबकुछ अनंत शून्य से पैदा होकर उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा गया है. इससे यह बात भी साफ हो जाती है कि पुराणों में लिंग के आदि अंत को खोजने संबंधी कथाओं का रहस्य यही है कि लिंग सीधे-सीधे यूनिवर्स या ब्रह्मांड की ही छाया है. मार्कण्डेय पुराण में जल को पहली सृष्टि और जल मध्य में ब्रह्मांड की स्थिति दिखाकर एक ही देव शरीर में ब्रह्मांड के उर्ध्व, मध्य और अधो भागों को दिखा उन्हें क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम दिया गया है.

शिवजी के बिना पूजा है अधुरी

कर्म पुराण में शिव स्वयं कहते हैं कि मैं ही विष्णु और देवी हूं. अतः आदि देव, सब देवों के देव, महादेव, त्रिदेव स्वयं शिव ही हैं. अंबिका सहित शिव पूजन में सब देवों की पूजा और इनकी पूजा नमस्कार के बिना बाकी देवों की पूजा की संपूर्णता की कल्पना करना ही गलत है, क्योंकि बिना इनकी पूजा के संपूर्णता हो ही नहीं सकती है. शिव को पंचमुख भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये पांच तत्व ही शिव के पांच मुख हैं. योग शास्त्र में पांच तत्वों के रंग लाल, पीला, सफेद, सांवला और काला बताया गया है. इनके नाम भी सद्योजात (जल), वामदेव (वायु), अघोर (आकाश), तत्पुरुष (अग्नि) और ईशान(पृथ्वी) हैं. अतः ब्रह्मांड के मानवीकरण और जीवन के योग-वियोग की स्थिति का कार्य स्वयं ही होने से पंचमुख होना बताया गया है.

पूजा घर से तुरंत हटा लें ये चीजें, छीन लेती हैं घर की सुख-शांति, कर देती हैं कंगाल!

श्री रोशनी शर्मा
9265235662
हस्त रेखा एवं फेस रीडर
(ज्योतिषाचार्य)

वास्तु शास्त्र में घर के हर हिस्से और चीजों के लिए नियम बताए गए हैं. यदि इन नियमों का पालन सही तरीके से ना किया जाए तो घर में वास्तु दोष पैदा होता है. जिससे घर में नकारात्मकता आती है. घर में झगड़े-कलह होते हैं, घर के लोगों की तरक्की रुक जाती है, गरीबी और बीमारियां घेर लेती हैं. घर का मंदिर या पूजा घर ऐसा ही बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है. देवी-देवताओं के इस घर में यदि छोटी सी भी गलती हो जाए तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है.

घर की सुख-शांति छीन लेगी ये गलती

घर में मंदिर का होना सकारात्मकता लाता है. लेकिन मंदिर में गड़बड़ी का होना बड़े नुकसान का कारण भी बनता है. ऐसे में जरूरी है कि पूजाघर से जुड़े कुछ जरूरी वास्तु के नियम जान लें. इसके अनुसार मंदिर में कुछ चीजों को रखना वर्जित बताया गया है.

- वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी देवी-देवताओं की रौद्र रूप वाली तस्वीरें या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए. ऐसा करने से घर में झगड़े-कलह बढ़ते हैं. घर में अशांति रहती है इसलिए पूजा घर में हमेशा देवी-देवताओं के सौम्य रूप वाली आशीर्वाद देती हुए मूर्ति-तस्वीरें ही रखना चाहिए.

- वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी खंडित मूर्ति या तस्वीरें नहीं रखें. ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है. हमेशा भगवान की अच्छी और सुंदर मूर्तियां या तस्वीरें ही रखें. ताकि उनके दर्शन करके सकारात्मक और सुकून की अनुभूति हो.

- कई बार लोग एक ही देवी-देवता की कई तस्वीर या मूर्ति पूजा घर में रख लेते हैं. जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए. विशेष तौर पर पूजा घर में 2 शिवलिंग गलती से भी ना रखें. ये गलती घर की सुख-समृद्धि छीन लेगी.

- कभी भी देवी-देवताओं की मूर्ति या चित्र आमने-सामने नहीं रखें. इससे घर में झगड़े-कलह होते हैं.

11 दिन तक लगातार कर लें हनुमान जी से जुड़ा ये काम, हर मनोकामना पूरी होने की है गारंटी

ज्योतिष शास्त्र में मंगलवार का दिन भगवान हनुमान की पूजा-पाठ और उपासना का दिन बताया गया है. कहते हैं इस दिन किए गए कुछ खास उपाय व्यक्ति के जीवन से दुखों का नाश करते हैं. साथ ही, लंबे समय से अधूरी मनोकामनाएं भी बजरंगबली पूर्ण करते हैं. मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने का विशेष महत्व बताया गया है. अगर आपकी भी ऐसी ही कोई मनोकामना है, जो आप पूरी करना चाहते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ विधि पूर्वक करने से विशेष लाभ होता है और व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है.

हनुमान चालीसा पाठ की सही विधि

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नानादि से निवृत्त हो हनुमान जी की तस्वीर स्थापित करें. इसके बाद एक थाली में फल और फूल की स्थापना करें. इसके बाद अपनी अधूरी मनोकामना या इच्छा हाथ जोड़कर हनुमान जी के आगे दोहराएं. इसके बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें.

- इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि हनुमान चालीसा की अंतिम चौपाई में संत तुलसीदास की जगह अपना नाम लें.

- कहते हैं कि इस उपाय को करते समय अपना नाम लेंगे, तो आपके सभी काम सिद्ध होंगे. बता दें कि ये उपाय आपको लगातार 11 दिन तक करना है.

- इस उपाय की शुरुआत मंगलवार के दिन से करना उत्तम रहता है. इसके बाद हनुमान जी की पूजा करें और फल का भोग लगाएं.

देश में बढ़ती महंगाई के बीच क्या पैकेज्ड फूड कंपनियां बढ़ाने जा रही हैं दाम?

मुंबई। एजेंसी

एक ओर जहां खाने-पीने की चीजों की महंगाई में तेजी जारी है तो दूसरी ओर पैकेज्ड फूड कंपनियों का दाम बढ़ाने का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा है। जबकि पिछले साल महंगाई बढ़ते ही लगभग सभी कंपनियों ने या तो दाम बढ़ा लिए थे या वही दाम रख कर उनका वजन कुछ कम कर दिया था। भारत में साज फूड्स के बिस्कुट और बेकरी ब्रैंड ैव ईस् के श्ऊ विजय कुमार सिंह का कहना है कि महंगाई बढ़ने से इस कैटिगरी पर दबाव साफ नजर आ रहा है। गांवों में डिमांड सुस्त पड़ी है और ग्रोथ में मुश्किल आ रही है। सिंह कहते हैं, 'अभी हम कमॉडिटी की कीमत में इजाफे का दबाव सहन कर रहे हैं। प्रॉफेटेब्लिटी अच्छी है और कंस्यूमर पर कोई बोझ नहीं डालन चाहते। वैसे भी अभी महंगाई का कोई खास असर हमारी कैटिगरी पर नहीं आया है। उम्मीद है कि नहीं आएगा, क्योंकि चुनावी साल में सरकार महंगाई को लेकर और ज्यादा सर्तक रहेगी। हमनें अभी सुपर फूड देशी घी के प्रॉडक्ट लॉन्च किए जिसे अच्छा रेस्पांस भी मिला है।

डिमांड पर आया था असर

हालांकि, इक्विनॉमिक्स रिसर्च के एमडी जी. चोकलिंगम ने बताया कि इस बार की महंगाई का दवाब पिछले साल से अलग है। इसलिए पैकेज्ड फूड कंपनियों ने दाम अभी तक नहीं बढ़ाए हैं। पिछले साल सभी तरह की कमॉडिटी के दाम बढ़े थे लेकिन इस बार दुनिया में आर्थिक सुस्ती के कारण कमोडिटी बास्केट का वह हिस्सा जो क्रूड से जुड़ा है उसमें गिरावट का ट्रेंड दिखा रहा है। वहीं, जो हिस्सा एग्री कमॉडिटी से जुड़ा है, वह बैमौसम बारिश और तुफानी मॉनसून के कारण धीरे-धीरे बढ़ रहा है। कंपनियां प्राइस को लेकर इसलिए भी बैकफुट पर हैं कि पिछले साल कीमतें बढ़ने से डिमांड पर असर आ गया था।

वेजिटेबल्स की कीमतें ज्यादा बढ़ीं

पारले प्रॉडक्ट्स के सीनियर कैटिगरी हेड मयंक शाह का कहना है कि फ्रूट और वेजिटेबल्स की कीमतें ज्यादा बढ़ी हैं। इससे हमारे ऊपर असर नहीं हुआ है। हमारे लिया ज्यादा असर खाद्य तेज, शुगर, मिल्क और गेहूं और मैदा आदि करता है। इनमें मिक्स्ड प्राइस ट्रेंड हैं। हालांकि, हम एग्री-कमॉडिटी में महंगाई पर करीबी नजर रख रहे हैं।

खाने का तेल हुआ महंगा

रिटेल ट्रेडर्स का कहना है कि खाने के तेल की कीमतें तो एक साल से भी कम समय में 50% कम हुई हैं, क्योंकि विकसित देशों में कंस्यूमर की ओर से डिमांड कम है और ऑइल सीड का प्रॉडक्शन भी अच्छा हुआ है। शक्कर 42-45 रुपये किलो के बीच स्टेबल चल रही है। ऐसे में कंपनियां अभी प्राइस को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहतीं।

दीपावली से पहले लाएंगे नई सहकारी नीति

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय सरकार दीपावली तक देश में नयी सहकारी नीति लेकर आयेगी। जो आने वाले 25 वर्षों के लिए सहकारिता का मानचित्र प्रस्तुत करेगी। लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर नारेबाजी कर रहे विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर-शराबे के बीच 'बहु राज्य सहकारी समितियां संशोधन विधेयक, 2022' पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यह बात कही। उन्होंने कहा, '' वर्ष 2003 के बाद से देश में कोई सहकारी नीति नहीं आई। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि विजयादशमी या ज्यादा से ज्यादा दीपावली तक हम नयी सहकारी नीति लेकर आएंगे। शाह ने कहा कि यह नयी सहकारी नीति आने वाले 25 वर्षों के सहकारिता का मानचित्र देश और दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करेगी। सहकारिता मंत्री ने यह भी कहा कि देश में सहकारी संस्थानों से जुड़ा कोई एकीकृत डाटाबेस नहीं था, ऐसे में मौजूदा संस्थानों और जहां पर सहकारी संस्थान नहीं है, उनका एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने का काम शुरू हो गया है।उन्होंने बताया कि इसका 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है और विजयादशमी के दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इसे ऑनलाइन जारी किया जायेगा।शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सहकारी शिक्षण के लिए आने वाले दिनों में सहकारिता विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है।

भारत को गैर-बासमती सफेद चावल से निर्यात प्रतिबंध हटाने के लिए 'प्रोत्साहित' करेगा आईएमएफ

वाशिंगटन। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कहा है कि वह भारत को चावल की एक निश्चित श्रेणी के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने के लिए ''प्रोत्साहित'' करेगा, क्योंकि इससे वैश्विक मुद्रास्फीति पर असर पड़ सकता है। भारत सरकार ने आगामी त्योहारों के दौरान घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और खुदरा कीमतों को काबू में रखने के लिए गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर 20 जुलाई को प्रतिबंध लगा दिया था। खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि गैर-बासमती उसना चावल और बासमती चावल की निर्यात नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। कुल निर्यात में दोनों किस्मों का हिस्सा बड़ा है। देश से निर्यात होने वाले कुल चावल में गैर-बासमती सफेद चावल की हिस्सेदारी लगभग 25 प्रतिशत है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे-ओलिवियर गौरींचस ने कहा कि मौजूदा स्थिति में इस प्रकार के प्रतिबंधों से बाकी दुनिया में खाद्य कीमतों में अस्थिरता पैदा होने की आशंका है और इसके बाद बाकी देश भी बदले में कोई कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, ''इसलिए हम भारत को निर्यात पर इस प्रकार से प्रतिबंध हटाने के लिए निश्चित ही प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि इनसे दुनिया पर हानिकारक असर पड़ सकता है.'' भारत से गैर-बासमती सफेद चावल मुख्य रूप से थाईलैंड, इटली, स्पेन, श्रीलंका और अमेरिका में निर्यात होता है।

त्योहारों से पहले सस्ता होगा गेहूं! सरकार यह कदम उठाने की तैयारी में

नई दिल्ली। एजेंसी

गेहूं के बढ़ते दामों की समीक्षा के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक अगले सप्ताह हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में गेहूं पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने का फैसला हो सकता है। दरअसल चुनावी साल में सरकार यह चाहती है कि त्योहारों में लोगों को सस्ता गेहूं मिले। अगर गेहूं की कीमतें बढ़ीं तो लोगों की नाराजगी से सरकार को दो-चार होना पड़ सकता है। गौरतलब है कि गेहूं की कीमत में पिछले एक साल में 5.79 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है। पिछले साल गेहूं 27.80 रुपये किलो था जो अब बढ़कर 29.41 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। मौजूदा समय में गेहूं के आयात पर 40 फीसदी ड्यूटी लगती है। इसमें साल 2019 से कोई बदलाव नहीं किया है। एक सीनियर अफसर का कहना है कि गेहूं की कीमतों को फेस्टिव सीजन के दौरान नियंत्रण में रखने के लिए सरकार कोई भी कदम उठा सकती है।

इस बीच कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार सभी जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों के साथ-साथ डिमांड और सप्लाई की स्थिति पर भी बारीकी से नजर रख रही है। सरकार ने कीमतों और उपलब्धता की स्थिति की नियमित निगरानी के लिए एक पैनल का गठन किया है। घ्ऊ की ओर से आयोजित मिलेट मिशन कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार खाद्य चीजों की उपलब्धता की स्थिति और उसके रिटेल कीमत के आधार पर निर्यात शुल्क लगाने या निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला करती है।

चावल के एक्सपोर्ट पर बैन

कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का मकसद है कि मोटे अनाज के तौर पर नजरअंदाज किए जाने वाले अनाज को दोबारा से आम उपभोक्ता, अमीर, गरीब सभी की थाली में पहुंचाया जाए। इस अवसर पर आईटीसी ने भारतीय डाक के साथ मिलकर मिलेट्स पर विशेष स्टाम्प जारी किया। सरकार ने हाल में गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर भी पाबंदी लगाई है। देश में हाल में चावल की कीमत में काफी तेजी आई है। इसे थामने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

लैब ग्रोन डायमंड के आगे फीका पड़ा असली हीरा

10 परसेंट तक गिर गया कारोबार

मुंबई। एजेंसी

रियल डायमंड के कारोबार में तकरीबन 10 पर्सेंट की गिरावट देखी जा रही है। इंडस्ट्री का कहना है कि अप्रैल के बाद एक्सपोर्ट में भी 10 पर्सेंट की गिरावट दर्ज हुई है। भारत डायमंड बोर्स के वाइस प्रेजिडेंट मेहुल भाई शाह का कहना है कि इसके पीछे अमेरिका, यूरोप और चीन में आर्थिक सुस्ती, रूस पर बैन से रफ डायमंड की सप्लाई में कमी आने से कारण अहम हैं। इसी के साथ लैब में तैयार किए जाने वाले डायमंड का बाजार जिस तेजी से उभरा है, इसका असर भी हुआ है। उदाहरण के लिए रियल डायमंड अगर पांच लाख रुपये का है, तो उसी के जैसा दिखने वाला लैब में तैयार डायमंड 20-40 हजार रुपये में मिल जाता है। यह बाजार नया है तो बढ़ रहा है। लैब ग्रोन डायमंड (LGD) लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। ये सिर्फ एक से चार सप्ताह में तैयार हो जाते हैं। ऐसे हीरों की बनावट, चमक, कलर, कटिंग, डिजाइन नैचुरल हीरे जैसी ही होती है और उसे भी सर्टिफिकेट के साथ बेचा जाता है।शाह ने बताया कि रियल डायमंड की कीमतें भी थोड़ी नरम हुई हैं, लेकिन क्रिसमस तक बाजार में फिर से तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि, उव्ण के पूर्व चेयरमैन नितिन खंडेलवाल का मानना है कि ग्लोबली अब आज के दौर की पीढ़ी सगाई की अंगूठी के लिए असल डायमंड से दूर हो रहे हैं। लैब में तैयार हो रहे डायमंड का मार्केट 22 अरब डॉलर का है और इंडिया अपनी कारीगरी और वैल्यू एडिशन से इस बाजार पर अपना रुतबा जमा सकता है और यही हो भी रहा है। घरेलू खपत और ग्लोबल खपत में डबल डिजिट की ग्रोथ नजर आ रही है।

भारतीयों को चाहिए वैल्यू

जयपुर जेम्स के CEO सिद्धार्थ सचेती का कहना है कि भारतीय लोगों के लिए वैल्यू ज्यादा मायने रखती है। यहां लैब में तैयार डायमंड का मार्केट नौकरीपेशा लोगों में है, लेकिन वे भी अब वैल्यू को ध्यान से देख रहे हैं। हां, अमेरिका और यूरोपीय देशों में जिस तरह से इसकी पर्यावरण के नजरिए से सुरक्षित बताकर ब्रैंडिंग की गई है, यह बात खरीदारों को भा रही है, क्योंकि उनके लिए कीमत प्राथमिकता नहीं, बल्कि पर्यावरण के लिए सेफ चीज ज्यादा जरूरी

है।' सिद्धार्थ सचेती का कहना है कि लैब में तैयार हीरे में भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है और ऐसे में उसे भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं कहा जा सकता है। हां, लैब में तैयार डायमंड की तुलना क्यूबिक जरकोनिया से किया जा सकता है, क्योंकि वैल्यू तो आपको सिर्फ रियल डायमंड की ही मिलेगी। पीएनजी जूलर्स के प्रमुख सौरभ गाडगिल का मानना है कि महंगाई और ग्लोबल इकॉनमी में सुस्ती के कारण लोग खर्चे में कटौती को तवज्जो दे रहे हैं। रियल डायमंड महंगा होता है और उन्हें जब लैब वाले हीरे का ऑप्शन मिला तो वे इस ओर तेजी से आकर्षित हुए हैं।

जेएलआर इंडिया ने सालाना 102% की वृद्धि के साथ पहली तिमाही में अब तक की रिकॉर्ड बिक्री हासिल की

जेएलआर इंडिया की खुदरा बिक्री दोगुनी हुई

रेंज रोवर, रेंज रोवर स्पोर्ट और डिफेंडर की बिक्री में 209% की ऐतिहासिक वृद्धि

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

जेएलआर इंडिया ने वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 102% की वृद्धि के साथ कुल 1048 वाहनों की बिक्री की है। कंपनी ने पहली तिमाही में बिक्री का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन रेंज रोवर, रेंज रोवर स्पोर्ट और डिफेंडर की बिक्री में 209% की अभूतपूर्व वृद्धि के कारण संभव हुआ। तीनों मॉडलों में निरंतर मांग देखी जा रही है, जिनका मौजूदा ऑर्डर बुक में 78% का योगदान है।

जेएलआर इंडिया के प्रबंध निदेशक श्री राजन अंबा ने कहा, 'जेएलआर इंडिया ने वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में रिकॉर्ड बिक्री की है और हमारी मात्रा वित्त वर्ष 23 की पहली तिमाही की तुलना में दोगुनी हो गई है। यह प्रदर्शन जेएलआर ब्रैंड्स की असाधारण हिस्सेदारी और आधुनिक लक्जरी वाहनों के हमारे श्रेणी में अग्रणी कलेक्शन का प्रमाण है। हमारे समझदार ग्राहकों के बीच बढ़ती मांग के कारण, हमारी ऑर्डर बुक मजबूत बनी हुई है और इसमें वृद्धि हो रही है। हम अपनी भारत की आगे की कहानी को लेकर उत्साहित और आश्वस्त हैं।'

'बेहतरीन आधुनिक लक्जरी वाहनों के गौरवान्वित निर्माता के रूप में, हमने वृद्धि करना जारी रखा है, हम अपनी विशिष्ट डिजाइन लैंग्वेज और विश्व-स्तरीय सुरक्षा मानकों को प्रदान करने वाली मशहूर ऑल-टेरेन क्षमता को अपनाया है।'

वित्त वर्ष 23 की दूसरी छमाही में नई रेंज रोवर और नई रेंज रोवर स्पोर्ट के सफल लॉन्च और डिफेंडर को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के साथ, वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही के लिए ऑर्डर बुक में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 88इ का उछाल आया है। मौजूदा ऑर्डर बुक छह महीने से अधिक की बिक्री को कवर करती है और इसमें महीने-दर-महीने लगातार वृद्धि देखी जा रही है। वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में जेएलआर प्रमाणित प्रि-ओन्ड बिजनेस में 137% की वृद्धि हुई है, जो एक बार फिर भारत में जेएलआर ब्रैंड्स की बढ़ती मांग और हिस्सेदारी को दर्शाता है। कंपनी के पास वर्ष के लिए निर्धारित उत्पाद पहलों की एक प्रभावशाली श्रृंखला है, जिसकी शुरुआत बेहतरीन रेंज रोवर वेलार की बहुप्रतीक्षित रिलीज से हो चुकी है, जिसके लिए बुकिंग हाल ही में शुरू हुई है। जेएलआर ने हाल ही में अपनी नई कॉरपोरेट पहचान और अपने हाउस ऑफ ब्रैंड्स नजरिये की घोषणा की है ताकि जेएलआर के प्रत्येक ब्रांड - रेंज रोवर, डिफेंडर, डिस्कवरी और जगुआर - के अनूठे डीएनए को सामने लाया जा सके। साथ ही कंपनी के दृष्टिकोण को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।

कॉटन उद्योग की हालत में आगामी महीनों के दौरान सुधार आने की उम्मीद

मुम्बई । एजेंसी

पिछले वित्त वर्ष के अत्यन्त कमजोर प्रदर्शन के बाद स्वदेशी कॉटन उद्योग को चालू वित्त वर्ष में कारोबार कुछ सुधरने की उम्मीद है। पिछले साल के मुकाबले इस बार कॉटन उत्पादों की बिक्री में मात्रा की दृष्टि से 5-7 प्रतिशत का इजाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। उद्योग समीक्षकों के अनुसार भारतीय रूई का भाव गिरकर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य के निकट आ गया है और प्रतिस्पर्धी देशों से इसकी मांग बाहर निकल कर भारतीय बाजार की तरफ मुड़ने लगी है। चीन सहित कई अन्य देशों में कॉटन यार्न एवं फैब्रिक्स की अच्छी मांग देखी जा रही है। इधर घरेलू प्रभाग में त्यौहारी सीजन के दौरान वस्त्र उत्पादों की मांग बेहतर रहने की उम्मीद की जा रही है। इसी तरह वैश्विक स्तर पर निम्न तबके के उद्योगों में भी मांग सुधरने के आसार हैं जिससे भारतीय कॉटन उद्योग को कारोबार बढ़ाने का मजबूत आधार मिल सकता है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान उद्योग का प्रदर्शन कमजोर रहा था क्योंकि रूई (कपास) का घरेलू बाजार भाव उछलकर काफी नीचे स्तर पर पहुंच गया था।

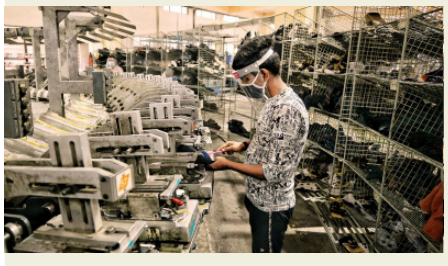

टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष का कहना है कि उद्योग अब धीरे-धीरे समस्याओं के भंवर से आगे निकल रहा है और आगामी महीनों में इसके कारोबार में अच्छी प्रगति होने की उम्मीद है। अगले महीने से शुरू हो रहे त्यौहारी सीजन में कॉटन उत्पादों की मांग में अच्छी बढ़ोत्तरी हो सकती है और खासतौर से रिटेल कारोबार में भारी इजाफा होने के आसार हैं। कपास का घरेलू बाजार भाव शीर्ष स्तर की तुलना में घटकर अब काफी नीचे आ गया है जिससे उत्पादों के लागत खर्च में कमी आ रही है और यह धीरे-धीरे वैश्विक बाजार में अन्य निर्यातक देशों की तुलना में प्रतिस्पर्धी हो रहा है।

ग्लोबल मार्केट में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है चावल की कीमत

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत द्वारा गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर पाबंदी लगाए जाने के साथ ही इसकी कीमत में भारी तेजी का अनुमान जताया जा रहा है। एशिया और अफ्रीका में अरबों लोगों का मुख्य भोजन है। चावल की कीमतों में बढ़ोतरी से इनफ्लेशन महंगाई दर पर भी दबाव बढ़ेगा और चावल खरीदने वाले देशों का आयात खर्च भी बढ़ेगा। भारत ने गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर रोक लगाई है, जिसका मकसद घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रित करना है। भारत सरकार ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है. जब अल-नीनो के असर की वजह से फसलों के उत्पादन में गिरावट की आशंका जताई जा रही है। साथ ही, यूक्रेन की निर्यात इकाइयों पर रूस के हमले से भी हालात खराब हुए हैं।

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमिरेट्स प्रोफेसर पीटर टिमर ने बताया, 'निर्यात पर रोक के भारत के फैसले को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। टिमर कई दशकों खाद्य सुरक्षा विषय पर काम कर रहे हैं। चिंता की बात यह भी है कि एशिया में जल्द ही चावल की कीमतें भारी तेजी के साथ नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं।'

चावल का एक और प्रमुख निर्यातक देश वियतनाम पहले ही सफेद चावल के लिए 600 डॉलर प्रति टन की कीमत मांग रहा है। थाइलैंड भी ऐसा ही कर सकता है। ऐसे में ही थाइलैंड के चावल की कीमत 2012 के बाद सबसे ज्यादा कीमत पर पहुंच जाएगी। थाइलैंड में चावल की कीमत फिलहाल 534 डॉलर प्रति टन है, जो 2 साल का उच्चतम स्तर है।

इस महीने चावल के अलावा गेहूं, मक्का और अन्य फसलों की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है जिससे ग्लोबल स्तर पर खाद्य पदार्थों की कीमतों में फिर से तेजी का रुझान दिख सकता है। फिलहाल, लंबे समय से इसमें गिरावट का ट्रेंड है। जून में संयुक्त राष्ट्र का फूड प्राइस इंडेक्स अप्रैल 2021 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। इस इंडेक्स में पिछली 5 तिमाहियों से गिरावट है।

कुछ किस्मों के चावल के निर्यात पर भारत की पाबंदियों की वजह से देश के कुल निर्यात में 30इ से 40इ तक की गिरावट हो सकती है। हालांकि, नोमूरा होल्डिंग्स इंक ने चेतावनी दी है कि बारिश में कमी और घरेलू इनफ्लेशन में बढ़ोतरी से चावल की अन्य कैटगरी के निर्यात पर भी रोक लगाई जा सकती है।

इन कदमों का असर चीन, मलेशिया, फिलिपींस, इंडोनेशिया और कई अफ्रीकी देशों पर भी पड़ सकता है। हालांकि, अलग-अलग देशों की खाद्य सुरक्षा की जरूरतों और उनकी सरकारों के अनुरोध पर भारत कुछ हद तक निर्यात की अनुमति दे सकता है। इसके अलावा, बासमती और एक अन्य कैटगरी के चावल के निर्यात की अनुमति अब भी मौजूद है, जिससे बाकी देशों को कुछ राहत मिल सकती है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित । संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।